प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 13 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 25 – 01 अप्रैल 2019 मूल्य पांच रूपए

क्या जयराम सरकार के मन्त्री भी आऊट सोर्सिंग के कारोबार में शामिल हैं

शिमला/शैल। अभी कुछ दिन पहले प्रदेश विश्वविद्यालय के समीप पॉटर हिल में आरएसएस की शाखा लगाने और क्रिकेट खेलने को लेकर

उठे विवाद में आरएसएस के स्वयंसेवकों, विद्यार्थी परिषद के छात्रों और एसएफआई के बीच खूनी झड़प हो गयी जिसमें इन तीनों संगठनों के करीब डेढ़ दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को आईजीएमसी और रिपन अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। यह पहला मामला है जहां इस तरह के संघर्ष में आरएसएस का नाम आया है। इस झगड़े के बाद दोनो पक्षों की ओर से पुलिस में मामले दर्ज करवाये गये हैं। मामले दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिये कारवाई में जुट गयी है। इस संघर्ष में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें डाक्टरों की निगरानी में रखा गया है। इस मामले पर मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर से लेकर शिक्षा मन्त्री सुरेश भारद्वाज और एसएफआई तथा नौजवान सभा के नेता आमने –सामने आ गये हैं। प्रदेश सीपीएम के शीर्ष नेतृत्व ने इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता करके सरकार और मुख्यमन्त्री की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाये हैं। आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय का भगवाकरण किया जा रहा है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को लेकर चुनाव आयोग तक से शिकायत की गयी है।

नौजवान सभा के संयोजक चन्द्रकांत वर्मा ने आरोप लगाया है कि इस खूनी झड़प का मूल कारण विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आऊट सोर्स पर की गयी भर्तियां हैं। उसके मुताबिक आऊट सोर्स पर भर्तीयां करने के लिये टैण्डर मंगवाये गये थे और भर्ती का ठेका किसी कारपोरेट नामक कंपनी को दे भी दिया गया था। लेकिन इस ठेके को बाद में शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप से रद्द कर दिया गया। बाद में फिर टैण्डर मांगे गये और इस बार सिंगल टैण्डर पर ही एक उत्तम हिमाचल नामक कंपनी को यह ठेका दे दिया गया। यह उत्तम हिमाचल कंपनी शिक्षा मंत्री के किसी करीबी की बताई जा रही है। आऊट सोर्स के माध्यम से विश्वविद्यालय की परिणाम शाखा में 18 प्रोग्रामर भर्ती किये गये हैं। आरोप है कि यह सारे लोग भाजपा और आरएसएस से संबद्ध लोग हैं। इन लोगों के भर्ती होने से परिणामों की निष्पक्षता प्रभावित होने का सन्देह व्यक्त किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय की परिणाम शाखा एक गोपनीय प्रभाग मानी जाती है जिसमें गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसे में यह पहला सवाल उठता है कि क्या इस शाखा में गोपनीयता का काम आऊट सोर्स पर तैनात किये गये कर्मचारियों को सौंपा जा सकता है। आऊटसोर्स पर सेवा उपलब्ध करवाने वाली कंपनी शिक्षा मन्त्री के करीबी की कही गयी है। इसका कोई खण्डन नही आया है। यह सरकार भी अपने विभिन्न अदारों में आऊट सोर्स पर भर्तीयां कर रही है। विश्वविद्यालय के इस विवाद से पहले राज्य बिजली बोर्ड में आऊट सोर्स के टैण्डर को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। अभी आऊट सोर्स कर्मी कालीबाड़ी में एक सम्मेलन करके आन्दोलन की रूप रेखा तैयार कर चुके हैं। जयराम के एक मन्त्री के तो इस संबंध में पत्र भी छप चुके हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के कुछ मन्त्री इस आऊट सोर्स नीति को अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इस संद्धर्भ में सरकार की नीयत और नीति पर उस समय शक हो जाता है जब सरकार आऊट सोर्स को लेकर विधानसभा में पूछे गये सवालों को यह कहकर लंबित कर देती है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। जब सरकार आऊट सोर्स पर भर्तीयां कर ही रही है फिर इसमें पूरी सूचना सार्वजनिक रूप से सामने न रखना सवाल तो खड़े करेगा ही। क्योंकि इन भर्तीयों में शैक्षणिक मैरिट और आरक्षण के तहत रोस्टर आदि की अनुपालना करने की कोई बंदिश नही रहती है। और ठेकेदार को बिना किसी काम के मोटा कमीशन मिलता रहता है। यह कंपनी अपने दफ्तर का काम भी केवल एक बोर्ड टांगकर ही चला लेती है। न्यू शिमला में इस तरह की एक कंपनी का बोर्ड काफी चर्चा में रहा है।

इस परिदृश्य में आज यह एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है कि जो लाखों लोग रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नाम पंजीकृत करवाकर रोजगार की प्रतीक्षा में बैठे हैं उनका क्या होगा। इस समय प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 8,34084 लोग पंजीकृत हैं। जिनमें 73077 पोस्ट ग्रैजुएट, 1,32,186 ग्रैजुएट, 5,86,453 मैट्रिक, 40819 अन्य पढ़े लिखे और 1549 अनपढ़ है। लेकिन

11.2- REGISTRATION & PLACEMENTS DONE BY THE EMPLOYMENT EXCHANGES

XI- EMPLOYMENT [107

(Number)

Year	Candidates registered	Vacancies notified	Candidates placed	On live register at the end of the period
1	2	3	4	5
2005-06	1,69,623	4,674	4,763*	8,16,878
2006-07	1,49,012	6,132	6,127*	7,56,980
2007-08	1,46,519	4,358	4,697*	7,82,348
2008-09	1,67,437	7,287	7,381*	8,13,782
2009-10	1,30,480	4,235	4,080*	8,27,329
2010-11	1,20,042	6,732	4,368*	8,25,764
2011-12	1,35,781	10,573	11,620*	8,39,007
2012-13	1,68,779	5,611	11,309*	8,61,314
2013-14	2,77,903	5,777	8,485*	10,12,602
2014-15	1,77,309	4,381	9,089*	8,92,988
2015-16	1,99,892	3,486	7,347*	8,28,048
2016-17	1,77,441	5,624	5,243*	8,11,306
2017-18	2,06,664	8,462	5,297*	8,34,084

*Including Private Sector.
Source: - Directorate of Employment, Himachal Pradesh.

से स्पष्ट हो जाता है।

इसी के साथ यह आंकड़ा भी महत्वपूर्ण है कि इस सरकार में कुल पिछले पन्द्रह वर्षो में प्रतिवर्ष कितने लोगों को सरकार और प्राईवेट क्षेत्र में रोजगार मिल सका है यह सरकार के अर्थ एवम् संख्या विभाग के इन आंकड़ो 1,77,338 कर्मचारी नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं जबकि 42,877 कर्मचारी नियमित नही हैं। इन आंकड़े में वॉलंटियर, तदर्थ, विद्याउपासक, टैन्योर और कान्ट्रैक्ट आदि सब शामिल है इसमें आऊट सोर्स का आंकड़ा शामिल नही है क्योंकि आऊट सोर्स को सरकारी कर्मचारी की संज्ञा नही दी जा सकती। आज आऊट सोर्स कर्मचारियों की संख्या भी करीब पचास हजार का आंकड़ा छूने वाली है क्योंकि जब वीरभद्र सरकार के दौरान इन्हें नियमित करने की नीति बनाने की चर्चा उठी थी तब इनकी संख्या 35000 कही गयी थी। उसके बाद आजतक इसमें 15000 से अधिक और भर्ती होने की चर्चा है। ऐसे में आने वाले दिनों में विश्वविद्यालय की तरह और कहां–कहां क्या घट सकता है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इन आंकड़ो से सरकार के इन दावों का सच भी सामने आ जाता है कि कब कितना रोजगार मिला है।

अनिल बने भाजपा के गले की फांस

शिमला/शैल। जयराम के ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा के बेटे आश्रय मण्डी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी बन गए। आश्रय के कांग्रेस का उम्मीदवार होने से भाजपा के लिये अनिल शर्मा को मंत्रीमण्डल और पार्टी में बनाये रखना गले की फांस बनता जा रहा है। क्योंकि जब तक अनिल शर्मा भाजपा के लिखित आदेशों की अनुपालना करने से इन्कार नहीं करते हैं तब तक उनके खिलाफ दल बदल एंवम् अनुशासनहीनता के तहत कारवाई नही की जा सकती है। अभी तक सूत्रों के मुताबिक रिकार्ड पर ऐसा कुछ नही आया हालांकि अनिल शर्मा लोकसभा क्षेत्र के लिये आयोजित कार्यक्रम ''मै भी चौकीदार हूं'' में जाहू में शामिल नही हुए हैं। लेकिन इसके लिये कोई लिखित आदेश नही थे। ऐसे में अनिल शर्मा का निष्कासन पेचीदा होता जा रहा है। क्योंकि अनिल शर्मा मुख्यमन्त्री के अपने ही गृह जिला से ताल्लुक रखते हैं और वरिष्ठ मंत्री है। इस नाते उन्हें सरकार के अन्दर की जानकारियों का ज्ञान होना स्वभाविक है। फिर यह बाहर आ ही चुका है कि अनिल शर्मा मुख्यमन्त्री के सलाहकारों के प्रति बहुत सन्तुष्ट नही रहे हैं। इससे यह इंगित हो जाता है कि जब चुनाव के दिनों में भाजपा अनिल को बाहर करती है तब सरकार को लेकर बहुत सारी असहज स्थितियां पैदा हो सकती हैं।

अभी पंडित सुखराम को लेकर जिस तरह का ब्यान शान्ता कुमार का आया है उससे भाजपा पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब 1998 और 2017 में सुखराम का सहयोग भाजपा ने लिया था और उनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी तब सुखराम अच्छे थे और उससे भाजपा की कोई बदनामी नही हुई थी जो आज उनके भाजपा के साथ छोड़ने से हो गयी है। यह निश्चित है कि भाजपा जितना ज्यादा सुखराम और अनिल को कोसेगी उतना ही ज्यादा भाजपा का नुकसान होगा। आज राजनीतिक परिस्थितियों में विष्लेशकों के मुताबिक अनिल शर्मा को यह सुनिश्चित करना है कि भाजपा जल्द से जल्द उन्हें पार्टी से निकाले और वह खुलकर बेटे के लिये चुनाव प्रचार करें। अभी अनिल शर्मा के खिलाफ संगठन की अनुशंसा पर दल बदल कानून के तहत कितनी कारवाई संभव है इस पर स्थिति स्पष्ट नही है। क्योंकि संगठन में लोकतान्त्रिक अधिकारों के तहत मत भिन्नता की पूरी छूट रहती है। आज जब पूरी भाजपा ''मै भी चौकीदार हूं'' हो रही है तब इसके कई वरिष्ठ सांसदों/मन्त्रीयों ने चौकीदार होने से मना कर दिया है। यह कार्यक्रम संगठन का है और इसे न मानने से दल बदल के तहत कारवाही आकर्षित नही होती है। यह कारवाही सामान्यत: सदन में विहिप की उल्लघंना पर ही होती है और अभी प्रदेश विधानसभा का कोई सत्र होने नही जा रहा है। ऐसे में अनिल के लिये सदन की सदस्यता से वंचित होने और फिर उपचुनाव का सामना करने की स्थिति लोकसभा चुनावों के बाद ही आयेगी ऐसे में यह भाजपा को देखना है कि वह अनिल के निष्कासन का जोखिम अभी उठाती है या बाद में।

पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करें ईको क्लब:आशुतोष गर्ग

शिमला/शैल। अतिरिक्त उपायुक्त मण्डी आशुतोष गर्ग ने जिला के सभी ईको क्लब प्रभारियों से पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वच्छता को लेकर अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने का आह्वान किया है। वे शिक्षा विभाग

द्वारा ईको क्लब प्रभारियों के क्षमता विकास के लिए उपायुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे।

यह कार्यशाला केंद्रीय पर्यावरण, वानिकी व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य विज्ञान प्रोद्यौगिकी एवं पर्यावरण परिषद शिमला ने संयुक्त रूप से आयोजित की। कार्यशाला में शिक्षा खण्ड बल्ह व सदर के 80 ईको क्लबों के प्रभारियों ने भाग लिया।

आशुतोष गर्ग ने कहा कि मण्डी जिला में 250 स्कूलों में ईको क्लब गठित किए गए हैं। स्कूलों में गठित ईको क्लब के माध्यम से बच्चों की पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामाजिक दायित्व को लेकर लोगों को जागरूक करने में बड़ी भूमिका है। यह क्लब ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाने में सहायक रहे हैं।

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलाव से प्रकृति प्रभावित हो रही है। कभी बाढ़-सूखे जैसे संकट पैदा हो रहे हैं। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अपने दायित्व को लेकर हमें विचार-चिन्तन करने की आवश्यकता है। इसके लिए कारगर कदम उठाना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि जिला में ठोस कूड़ा कचरा प्रबन्धन के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। हिमाचल में प्लास्टिक का प्रयोग बन्द है लेकिन अन्य कई राज्यों में इस पर प्रतिबन्ध न होना एक समस्या है। इस समस्या पर गंभीर चिन्तन व ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर उप-निदेशक उच्च शिक्षा अशोक शर्मा ने बताया कि 30 मार्च को मण्डी जिला के हर ईको क्लब में पृथ्वी की सुरक्षा के लिए 60 मिनट तक चलने वाले अभियान के तहत पर्यावरण प्रदूषण व कचरे को न फैलाने का संकल्प लिया जाएगा।

उप-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा पी.सी. राणा ने जिला मण्डी में ईको क्लब के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यों की विस्तृत जानकारी दी व प्रभारियों को प्रकृति को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।

राज्य विज्ञान प्रोद्यौगिकी एवं पर्यावरण परिषद शिमला की प्रतिनिधि एवं कार्यक्रम समन्वयक अक्षिता ने बताया कि मण्डी जिला के समस्त स्कूलों में ईको क्लब गठित किए जाएंगे।

कार्यशाला में आईआईटी मण्डी के डॉ. दीपक स्वामी और डॉ. उदय ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां एवं आशीष शाह ने सौर उर्जा आदि विषयों पर बतौर स्त्रोत व्यक्ति ऊर्जा अपने विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर आईएएस प्रोबेशनर निवेदिता नेगी, कार्यशाला समन्वयक संजीव ठाकुर सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

वनों को लगने वाली आग पर काबू पाने में सभी व्यस्क पुरुषों की जिम्मेदारी तय

सोलन/शैल। आगामी गर्मी के सीजन में वनों को लगने वाली आग की घटनाओं पर काबू पाने के मकसद से जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। उपायुक्त विनोद कुमार द्वारा जारी आदेश में जिला के सभी गांवों के वयस्क पुरुषों की यह जिम्मेदारी तय की गई है कि इस तरह की घटनाओं के दौरान वे पैट्रोलिंग के अलावा अपनी सक्रिय भागीदारी भी निभाएंगे ताकि वन संपदा के अलावा सार्वजनिक संपत्ति को आग के चलते होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। ये आदेश हिमाचल प्रदेश विलेज एंड स्मॉल टाउन पेट्रोल एक्ट-1964 के तहत जारी किया गया है। आदेश 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक पूरे जिले में लागू रहेगा।

लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार चुनाव प्रचार पर खर्च सकेंगे अधिकतम 70 लाख

मण्डी/शैल। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार प्रचार पर अधिकतम 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। उन्हें खर्चे का ब्यौरा निर्वाचन विभाग को देना होगा, इसके अलावा आयोग द्वारा गठित टीमें भी प्रत्याशियों के खर्चों पर नजर रखेंगी। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी चुनाव खर्च निगरानी समिति आशुतोष गर्ग ने चुनाव खर्च निगरानी समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

आशुतोष गर्ग ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक प्रत्याशी को बैंक में नया खाता खुलवाना होगा। यह खाता उम्मीदवार अपने ऐजेंट के साथ संयुक्त रूप से भी खोल सकते हैं। उन्होंने बैंक अधिकारियों को उम्मीदवारों के खाता खोलने के लिए बैंक में अलग से काउन्टर स्थापित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बैंक अधिकारियों को उम्मीदवारों के प्रतिदिन खर्चे पर नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार एकमुश्त एक लाख या इससे ज्यादा राशि बैंक से निकालता है तो इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी या नोडल अधिकारी को अवश्य दें।

उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को सभी तरह की अदायगी चौक के माध्यम से करनी होगी। उपयोग से सम्बन्धित व्यय के लिए उपयोग की जाने वाली धन राशि को लाने-ले जाने वाले व्यक्ति के पास पहचान पत्र होना व धन के उपयोग सम्बन्धी कागजात साथ होना भी अनिवार्य है।

बैठक में एस.के. सिन्हा, डी.एस. कॉपरेटिव बैंक, डी.एस.ठाकुर, प्रबन्धक एसबीआई सुखविन्द्र पाल, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया विजय गौतम, तहसीलदार निर्वाचन राजेश तोमर सहित बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।

अधिकारियों–कर्मचारियों को क्षेत्र से बाहर जाने से पहले लेनी होगी अनुमति

शिमला/शैल। आईआईआईटी ऊना का प्रथम दीक्षांत समारोह एनआईटी हमीरपुर में मनाया गया। स्नातक दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि प्रो.एस.वी. राघवन (पूर्व वैज्ञानिक सचिव, कार्यालय प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार) ने प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को मेडल

व डिग्रियाँ देकर अलंकृत किया। इस मौके पर आईआईआईटी ऊना के निदेशक सेल्व कुमार ने प्रोफेसर टिमोथी, निदेशक आईआईटी मंडी, एचपीयूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. सिकंदर कुमार तथा एचपीटी यू हमीरपुर के वाइस चांसलर प्रो.एसपी बंसल का स्वागत किया। समारोह की शुरूआत सरस्वती वंदना से हुई और इसके बाद निदेशक आईआईआईटी ऊना द्वारा संस्थान की रिपोर्ट पेश की गई। आईआईआईटी ऊना ने अनुसंधान गतिविधियों को मजबूत करने के लिए आईआईटी मंडी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। निदेशक आईआईआईटी ऊना ने बताया कि वे जल्द ही पीएचडी कार्यक्रम भी शुरू करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि आईआईआईटी ऊना के स्थायी कैंपस का काम चल रहा है और वे 2022 तक उस कैंपस में शिफ्ट हो जाएंगे। इस दिन 2014-18 बैच के 49 छात्रों ने अपनी डिग्री प्राप्त की। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजिनियरिंग में अंकिता मेहरा को गोल्ड मेडल, छवि गर्ग को सिल्वर व अवनी बरमीचा को ब्रांज मेडल दिया गया। बीटेक इलैक्ट्रानिक कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में वर्तिका टंडन को गोल्ड मेडल, थोतकुरा अनिरूद्ध को सिल्वर मेडल व रोशन कुमार को ब्रांज मेडल से सम्मानित किया गया। बीटेक कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अनय बिस्वास, शिवी वत्स, अंकिता गुप्ता, अंकिता मिश्रा, दीपक कपासिया, रवि कुमार, गौरव यादव, दिनेश कुमावत, अरविंद, शिवम किरोडीवल, शाहदाब रईस, विजय लक्ष्मी, शिवम त्रिपाठी, विवान, छवी गर्ग, अवनी बरमीचा, गगन दीप, आधार गुप्ता, आकाश ओझा, निशांत शर्मा, मरीनल वात्सय, प्रांजल गौर, अमित कुमार राय, अंकित कुमार राज, एम गोमत रेड्डी, ज्येश मेहरा, शिवम वर्मा का डिग्री दी गयी। वहीं बीटेक इलेक्ट्रानिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में निहाल भारद्वाज, विपिन कुमार, रजत बंसल, कुशाग्र दोरिया, शुभम गोयल, कार्तिम पाठक, अमनी प्रीत बमानिया, थोताकुरा अनिरूद्ध, चंद्र मोहन शर्मा, शिवशंकर सियाग, देवी दन दित्ता, आकाश कुमार, मोहन सूंकर, अंजनी कुमारी, अविनाश सिंह, रोशन कुमार, लता मीना, राकेश कुमार सैनी, प्रवन पाडेय, हर्ष वर्मा, वर्तिका टंडन, किरण श्रीकुमार को डिग्री दी गयी।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक- जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार- ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष जागरूकता शिविर 5 अप्रैल से:उपायुक्त

शिमला/शैल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि आगामी लोकसभा निर्वाचन-2019 के दृष्टिगत जिला हमीरपुर में दिव्यांग मतदाताओं को प्रोत्साहित व जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं की शत-प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान विभिन्न स्तरों पर चलाया जा रहा है। हमीरपुर जिला में 21 जनवरी, 2019 तक 2,573 दिव्यांग मतदाता के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं और नए मतदाताओं को भी इसमें सम्मिलित करने का कार्य जारी है। उन्हें मतदान के लिए जागरूक व प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रवण दोष से पीड़ित दिव्यांग मतदाताओं के लिए 5 अप्रैल, 2019 से विशेष जागरूकता शिविर उपायुक्त कार्यालय के कक्ष (कमरा) संख्या 220 में आयोजित किया जा रहा है। इसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाल्टी में नियुक्त विशेष शिक्षिका (श्रवण क्षीणता) नीलम कुमारी इस श्रेणी के दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक व शिक्षित करेंगी। उन्होंने सभी सहायक निर्वाचन अधिकारियों से आग्रह किया कि वे बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांग मतदाता जागरूक हो सकें। उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को भी अपने फील्ड कर्मचारियों के माध्यम से इस श्रेणी के मतदाताओं को शिविर के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने व इसका लाभ उठाने को कहा।

डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि विभिन्न मतदान केंद्रों में मतदान दिवस पर भी दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थाएं स्थापित की जा रही हैं। इसमें शौचालय व पेयजल सुविधा के लिए समुचित दिशा सूचक, छायादार स्थल, पंक्तिविहीन मतदान सुविधा, व्हील चेयर, 18 वर्ष से कम आयु के निष्पक्ष व स्वतंत्र स्वयंसेवकों की सहायता, परिवहन की सुगम व समुचित व्यवस्था सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्रों में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा (फर्स्ट एड) का भी प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने सभी दिव्यांग मतदाताओं व उनके परिजनों से आग्रह किया है कि वे उपायुक्त कार्यालय परिसर में लगाए जा रहे विशेष शिविर का भरपूर लाभ उठाएं।

मोदी सरकार ने युवा वर्ग के लिए शुरू की कई कल्याणकारी योजनाएं : जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन में भारतीय जनता युवा मोर्चा सोलन मंडल द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन एवं मतदाता सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में प्रत्येक कार्यो के लिए युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। इस बार लोकसभा चुनाव में भी युवा वर्ग की भूमिका अहम रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। मोदी सरकार ने युवा वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। उन योजनाओं से लाखों परिवार लाभान्वित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा को केंद्र में पुन: सत्तासीन बनाने के लिए युवा वर्ग की भूमिका अहम होगी और युवाओं में मोदी को पुन:देश की कमान संभालने के लिए काफी जोश व उत्साह भी है। आज मतदाताओं की एक ही आवाज है कि देश की कमान मजबूत नेतृत्व के हाथ में संभाली जाएगी और वह नेतृत्व नरेंद्र मोदी हैं।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने युवा एवं जुझारू नेता सुरेश कश्यप को प्रत्याशी घोषित किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सोलन युवा मोर्चा सुरेश को विजयी बनाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करेगा। उन्होंने जनता से आग्रह करते हुए कहा कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों, नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुँचाये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सोलन भाजपा विधानसभा चुनाव की कमी को लोकसभा चुनाव में अवश्य पूरा करेगी। उन्होंने स्थानीय जनता से आग्रह करते हुए कहा कि देश में पुन: मजबूत नेतृत्व चुनने के लिए इस संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी युवा नेता सुरेश कश्यप को ऐतिहासिक जीत दिलाएं।

इस अवसर पर पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप, शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप सहित भाजपा एवं भाजयुमो के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व अन्य उपस्थित रहे।

वोटर हैल्पलाईन 1950 को लोक मित्र केन्द्रों के साथ जोड़ा जाएगा

शिमला/शैल। मतदाताओं को विभिन्न निर्वाचन सेवाओं तथा न्यूनतम मूल्यों पर फार्म-6, 6ए, 7, 8, 8ए इत्यादि जैसे विभिन्न पंजीकरण फार्म को ऑनलाईन भरने की सुविधा लोक मित्र केन्द्रों में प्रदान की जाएगी। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने दी।

निर्वाचन पंजीकरण आवेदन फार्म के लेन-देन, मतदाना सूची की प्रति पेज प्रिंटिंग, मतदाता फोटो पहचान पत्र फार्म जमा करने, आवेदन की स्थिति का पता लगाने तथा शिकायतों के पंजीकरण का मूल्य एक रुपये से ज्यादा नहीं लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यदि आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन को सॉफ्ट कॉपी तथा फोटो सहित पंजीकरण के लिए जमा करवाया जाता है तो उसका मूल्य एक रुपये से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार वैब कैमरे के माध्यम से फोटो तथा अपलोडिंग के लिए दस्तावेजों की स्कैनिंग का मूल्य दो रुपये लिया जाएगा। हालांकि इन केन्द्रों में न ही आवेदक से फोटो की हार्ड कॉपी ली जाएगी तथा न ही कम्पयूटर में रखी जाएगी। लोकमित्र केन्द्रों में आवेदक को नए पंजीकरण के लिए जन्म तिथि का प्रमाण जमा करवाना होगा।

इन केन्द्रों के माध्यम से मतदाता फोटो पहचान पत्र बनवाने का मूल्य 30 रुपये से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। यह पहचान पत्र सात दिनों में बनाए जाएंगे तथा अतिरिक्त 8 दिनों के अन्दर आवेदक के घरद्वार पर प्रदान किए जाएंगे। यदि उपरोक्त समय सीमा का पालन नहीं किया गया तो लोक मित्र केन्द्रों को कोई भी मूल्य देय नहीं होगा। हालांकि यदि आवेदक स्वयं लोकमित्र केन्द्र से पहचान पत्र प्राप्त करता है तो इसका मूल्य 25 रुपये से ज्यादा नहीं लिया जाएगा।

लोकमित्र केन्द्र के सामने बोर्ड लगाकर तथा केन्द्र के भीतर पोस्टर, बैनर तथा प्रचार सामग्री प्रदर्शित कर लोकमित्र केन्द्रों को भारत निर्वाचन आयोग के सुविधा केन्द्रों के तौर पर लोकप्रिय बनाया जाएगा। निर्वाचन डाटा, राष्ट्रीय शिकायत निवारण सेवाएं (एनजीसी) तथा वोटर हैल्पलाईन 1950 को लोक मित्र केन्द्रों के साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता पंजीकरण केन्द्रों, बूथ स्तरीय अधिकारियों तथा अन्य निर्वाचन अधिकारियों के वर्तमान तंत्र के माध्यम से सभी नागरिकों को नि:शुल्क सेवाएं उपलब्ध होंगी तथा सभी उपायुक्तों/उपमण्डली न्यायाधीशों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

स्वच्छता के लिए वार्ड कमेटियां गठित करने के निर्देश

शिमला/शैल। ग्रीन ट्रिब्यूनल की राज्य समिति की चेयरपर्सन राजवंत संधू ने कहा कि स्वच्छता के लिए सभी शहरी निकायों में वार्ड कमेटियां गठित की जाएं इसके साथ ही इन कमेटियों के माध्यम से ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाए। इस बाबत धर्मशाला के डीआरडीए के सभागार में ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन को लेकर शहरी निकायों तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी आयोजित की गई। इसमें शहरी निकायों में ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन को लेकर उठाए गए कदमों की समीक्षा भी की गई।

राजवंत संधू ने कहा कि शहरी निकायों के लिए ठोस कूड़ा प्रबंधन तथा स्वच्छता के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर तरल तथा ठोस कूड़ा कचरा एकत्रित करने के लिए भी उचित कदम उठाए जाएं ताकि संयंत्र में तरल तथा ठोस कूड़ा कचरा का सही तरीके से उपयोग हो सके। उन्होंने कहा कि स्कूलों में छात्रों को स्वच्छता प्रहरी भी बनाया जाए जो अपने अपने घरों में स्वच्छता को लेकर अभिभावकों सहित आस पास के लोगों को जागरूक कर सकें।

संधू ने कहा कि सभी शहरी निकायों को आधुनिक तकनीक के ठोस कूड़ा कचरा निष्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि किसी भी स्तर पर गंदगी नहीं रह सके। उन्होंने कहा कि निजी शैक्षणिक संस्थानों तथा शापिंग मॉल, होटल प्रबंधन संस्थानों को भी अपने अपने स्तर पर ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि खड्डों तथा नदियों में भी किसी तरह से पानी के बहाव के साथ कूड़ा कचरा नहीं पहुंचे इस के लिए भी आवश्यक प्लान तैयार किया जाए।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों तथा पर्यटन स्थलों के लिए भी कूड़ा एकत्रिकरण की दिशा में प्लान तैयार किया जाना जरूरी है।

इससे पहले उपायुक्त संदीप कुमार ने कांगड़ा जिला में स्वच्छता तथा कूड़ा कचरा प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

इस अवसर पर शहरी विकास विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी एस शांडिल सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे।

मना नहीं कर सकते विवाह पंजीकरण को पंचायत सचिव

मण्डी/शैल। जिला पंचायत अधिकारी सतीश कुमार अग्रवाल ने कहा कि पंचायत सचिव विवाह पंजीकरण को लेकर मना नहीं कर सकते। पंचायत सचिव पंचायत रजिस्टर में विवाह पंजीकरण करने के बाद उस पंचायत कार्यालय को सूचित करें कि अमुक युवती अथवा महिला का नाम विवाह के उपरांत इस पंचायत के अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है ताकि पूर्व पंचायत के अभिलेख से उसका नाम हटाया जाए।

जिला पंचायत अधिकारी ने ये बात धर्मपुर विकासखंड के पंचायत सचिवों के लिए आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि यदि महिला विदेशी मूल की हो तो विवाह को सम्बंधित उपमंडल के एसडीएम कोर्ट में दर्ज हो जाने के बाद पंचायत सचिव पंचायत के परिवार रजिस्टर में दर्ज कर सकता है। जिला पंचायत अधिकारी ने इस बात पर भी जोर दिया कि ई-परिवार के अलावा अन्य सभी ई-सेवाओं को मेंटेन और कार्यान्वित करना सभी पंचायतें सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने पंचायत सचिवों को यह भी कहा कि वे सभी नियमों से अपने आप को अपडेट बनाए रखें ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।

यदि पंचायत स्तर पर किसी तरह की कोई शंका हो तो क्लेरिफिकेशन को लेकर जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय को अवगत करवाएं। जिला पंचायत अधिकारी ने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र का सबसे छोटा किंतु महत्वपूर्ण अंग है। ग्रामीण विकास और लोगों के कल्याण में पंचायतें अहम भूमिका अदा करती हैं। ऐसे में जरूरी है कि पंचायती राज प्रतिनिधि और पंचायत सचिव अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी करें। उन्होंने कहा कि विशेषकर प्रिया सॉफ्ट की समीक्षा को लेकर अप्रैल माह के पहले सप्ताह में एक और समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

एच.आई.वी.रोकथाम पर अंतर-विभागीय बैठक आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की राज्य एड्स नियंत्रण सोसाईटी ने एच.आई.वी/एड्स की रोकथाम के लिए शिमला में एक अंतर-विभागीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं राज्य एड्स नियंत्रण सोसाईटी के अध्यक्ष आर.डी. धीमान ने की। इस बैठक में एच.आई.वी. से सम्बन्धित विभिन्न सामाजिक, आर्थिक घटकों पर विचार किया गया।

सभी सम्बन्धित विभागों तथा संगठनों की इस बैठक में एच.आई.वी. होने के खतरे को कम करने तथा इससे पीड़ित व प्रभावित लोगों पर इसके प्रभाव में कमी लाने को मिली बहुक्षेत्रीय प्रतिक्रिया पर विचार किया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने अपने सम्बोधन में कहा कि विभिन्न विभाग एड्स पर नियंत्रण तथा रोकथाम के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है, जिससे देश में वर्ष 2030 तक एड्स उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

बैठक में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम पर प्रस्तुति प्रस्तुत करने के अलावा नोडल अधिकारियों के नामांकन, संवेदनशीलता सत्र, 'नो यूअर स्टेट्स' जैसे अभियान, विश्व रक्तदान दिवस जैसे विशेष दिवसों को मनाने, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत एच.आई.वी. रोकथाम गतिविधियों को शामिल करने पर विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

नाकेबन्दी के दौरान 3.26 लाख की नकदी, 971.053 लीटर शराब जब्त

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस, आबकारी तथा आयकर विभाग द्वारा गठित दस्तों द्वारा प्रदेश में की गई संयुक्त नाकेबन्दी के दौरान 3,26,485 रूपये की नकदी, 971.053 लीटर शराब, बीयर तथा लाहण इत्यादि के अतिरिक्त 0.005001 किलोग्राम हेरोईन तथा 0. 12556 किलोग्राम चरस जब्त की गई।

पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस के पास 4717 लाईसेंस प्राप्त हथियार जमा हुए और अब प्रदेश में कुल 51,929 हथियार जमा किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न असामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित 21 व्यक्तियों की पहचान की गई और अब तक कुल 1154 व्यक्ति पकड़े जा चुके हैं। प्रवक्ता ने बताया कि उनके कार्यालय में प्राप्त कुल 7 शिकायतों में सभी शिकायतें आम जनता से प्राप्त हुई और अब तक प्राप्त कुल 97 शिकायतों में से 38 का निपटारा कर दिया गया है और शेष 59 शिकायतें सम्बन्धित विभागों को आगामी कार्रवाई हेतु भेजी गई हैं।

उन्होंने बताया कि जिलों में भी कुल 50 शिकायतें मिली हैं जिनमें से 24 का निपटारा किया जा चुका है और शेष 26 शिकायतों में कांगड़ा जिला 7, मण्डी 5, शिमला 1, हमीरपुर 4, ऊना 3, बिलासपुर 3, सोलन 2 तथा सिरमौर जिला में 1 शिकायत शामिल हैं।

अच्छे कार्य जीवन को महान बनाते है, यह मत भूले की जीवन अस्थायी है, इसलिए जीवन के हर क्षण का उपयोग किया जाना जरूरी है मौत आ जाएगी तो फिर कुछ भी न रहेगा, न यह शरीर, न कल्पना, न आशा। हर चीज़ मौत के साथ दम तोड़ देगी..... ''चाणक्य''

सम्पादकीय

जब प्रधानमन्त्री ही भाषायी मर्यादा लांघ जाये

आज प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी से लेकर कार्यकर्ता तक पूरी भाजपा ''मै भी चौकीदार'' हो गयी है। 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब देश की जनता ने इन लोगों को जन प्रतिनिधि के रूप में चुनकर देश की सत्ता सौंपी थी। देश की जनता ने इन पर इनके द्वारा किये गये वायदों पर विश्वास करके इन्हें सत्ता सौंपी थी। लेकिन आज इस कार्यकाल का अन्त आते तक यह सब चौकीदार हो गये हैं। देश की जनता ने अपना वोट देकर इन्हें प्रतिनिधि चुना था चौकीदार नहीं। चौकीदार मतदान के माध्यम से नही चुना जाता उसके चयन की एक अलग प्रक्रिया रहती है। लेकिन अब जब यह सब चौकीदार हो गये हैं तब इन्हें चौकीदार की चयन प्रक्रिया की कसौटी पर जांचना आवश्यक हो जाता है। इस जांच –परख के लिये ही मैने पिछली बार ''अब देश का चौकीदार ही सवालों में'' अपने पाठकों के सामने एक बहस उठाने की नीयत से रखा था। बहुत सारे पाठकों ने मेरे दृष्टिकोण को समर्थन दिया है तो कुछ ने उससे तलख असहमति व्यक्त की है। इस असहमति के आधार पर मैं इस बहस को आगे बढ़ा रहा हूं।

मेरा स्पष्ट मानना है कि जब सत्ता की जिम्मेदारी उठाने वाले लोग स्वयं चौकीदार का आवरण ओढ़कर सत्ता से जुड़े तीखे सवालों से बचने का प्रयास करेंगे तब यह लोकतन्त्र के लिये एक बड़ा खतरा हो जायेगा। सत्ता पक्ष होने के नाते यह इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि यह देश के ''जान और माल' की रक्षा करते और अपने पर उठने वाले हर सन्देह और सवाल की निष्पक्ष जांच के लिये अपने को प्रस्तुत करते। देश जानता है कि जब 2014 में सत्ता संभाली थी तब सत्ता पक्ष के कई जिम्मेदार लोगों के ऐसे ब्यान आने शुरू हो गये थे कि इनसे वैचारिक असहमति रखने वाले हर आदमी को पाकिस्तान जाने का फरमान सुना देते थे। इन्ही फरमानों के कारण लोकसभा में प्रचण्ड बहुमत हासिल करने के बाद दिल्ली विधानसभा चुनावों में केवल तीन सीटों पर सिमट कर रह गये। दिल्ली की हार के कारणों का सार्वजनिक खुलासा आज तक सामने नहीं आ पाया है। 2014 के चुनावों में और उससे पूर्व उठे भ्रष्टाचार के तमान मुद्दो का प्रभाव था कि देश की जनता ने तत्कालीन यूपीए सरकार को भ्रष्टाचार का पर्याय मानकर सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन एनडीए के पूरे शासन काल में भ्रष्टाचार के उन मुद्दों पर दोबारा कोई चर्चा तक नही उठी। लोकपाल की मांग करने वाले अन्ना हजारे तक उन मुद्दों को भूल गये। बल्कि जब टूजी स्पैक्ट्रम घोटाले पर अदालत में यह आया कि यह घोटाला हुआ ही नही है तब किसी ने भी इसपर कोई सवाल नही उठाया। 1,76,000 करोड़ का आंकड़ा देने वाले विनोद राय तक को किसी ने नही पूछा जबकि इसी घोटाले में यूपीए में शासनकाल में बड़े लोगों की गिरफ्तारी तक हुई थी। क्या अब इस घोटाले में कुछ कंपनीयों और बड़ों को बचाया गया है? यह सवाल उठ रहा है और कोई चौकीदार इसका जवाब नही दे रहा है। कॉमनवैल्थ गेम्ज़ घोटाले पर 2010 में आयी रिपोर्ट पर क्या कारवाई हुई है। इसका कोई जवाब नही आ रहा है। आज लोकपाल की नियुक्ति से पहले भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम का संशोधन कर दिया गया है। क्या आज इस संशोधित अधिनियम के बाद कोई भ्रष्टाचार की शिकायत कर पायेगा? इस संशोधन पर उठे सवालों का प्रधान चौकीदार से लेकर नीचे तक किसी ने कोई जवाब नही दिया है। क्या इन सवालों पर इन चौकीदारों की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिये। क्या आज चुनाव से पहले यह सवाल पूछे नहीं जाने चाहिये?

आज जब भाजपा ''मै भी चौकीदार'' अभियान छेड़कर कांग्रेस से पिछले साठ सालों का हिसाब पूछने जा रही है तब क्या उसे यह नहीं बताना चाहिये कि 2014 में उसने वायदा क्या किया था? क्या तब देश से यह नहीं कहा गया था कि हम सबकुछ साठ महीनों में ही ठीक कर देंगे। तबकी यूपीए सरकार को बेरोजगारी और महंगाई पर किस तरह कोसा जाता था लेकिन आज जब इन मद्दों पर सवाल पूछे जा रहे हैं तब कांग्रेस के साठ सालों की बात की जा रही है। क्या 2014 में देश से यह कहा गया था कि जो कुछ साठ सालों में खराब हुआ है उसे ठीक करने के लिये हमें भी साठ साल का ही समय चाहिये। तब तो साठ साल बनाम साठ महीनों का नारा दिया गया था। आज तो यह हो रहा है कि जब कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है तब हमें भी भ्रष्टाचार करने का लाईसैन्स मिल गया है। आज रोजगार के नाम पर हर काम को हर सेवा को आऊट सोर्स से करवाया जा रहा है। इस बढ़ते आऊट सोर्स पर तो अब यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि जब सरकार कोई भी सेवा स्वयं देने में असमर्थ है तब क्या सरकार को भी आऊट सोर्स से ही नहीं चलाया जाना चाहिये।

आज चुनाव होने जा रहे हैं इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि चोरी के आरोपों को चौकीदारी के आवरण में दबने न दिया जाये। क्योंकि जब सत्तारूढ़ भाजपा स्वयं 38 दलों के साथ गठबन्धन कर चुकी है तब उसे दूसरों के गठबन्धन से आपत्ति क्यों? अभी प्रधानमन्त्री ने सपा, आर एल डी और बसपा के गठबन्धन को शराब की संज्ञा दी है। क्या देश के प्रधानमन्त्री की भाषा का स्तर ऐसा होना चाहिये? इस संद्धर्भ में यदि कोई पूरी भाजपा के ''मैं भी चौकीदार'' होने को ''चोर मचाये शोर'' की संज्ञा दे डाले तो उसे कैसा लगेगा। यह सही है कि देश का बुद्धिजीवी वर्ग आज प्रधानमन्त्री की हताशा को समझ रहा है क्योंकि जिस तरह 2014 में लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे थे आज ठीक उसी तरह भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने का दौर चल पड़ा है और इससे हताश होना संभव है और उसे सार्वजनिक होने से रोकने के लिये किसी न किसी आवरण का सहारा लेना पड़ता है लेकिन एक सपूत को भाषायी मर्यादा लांघना शोभा नहीं देता। अपनी असफलताओं को भी स्वीकारने का साहस होना चाहिये क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई जैसे सारे मुद्दों पर पूरी तरह असफल हो चुकी है। जिस सरकार को जीडीपी की गणना के लिये तय मानक बदलना पड़ जाये उसके विकास के दावों पर कोई कैसे भरोसा कर पायेगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

आखिर इस आम चुनाव का मुख्य मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा किसान?

गौतम चौधरी

जिस खेती – किसानी के मुद्दे पर हाल ही में संपन्न पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़े गए, आखिर वे मुद्दे 2019 के संसदीय आम चुनाव से गायब क्यों है? अमूमन सत्तारूढ़ दल मुद्दों से भटकाने की योजना बनाती है क्योंकि वह सत्ता में है और उसके लिए ऐसा करना हितकर होता है लेकिन विपक्ष को क्या हो गया? उनके एजेंडों से भी खेती – किसानी गायब! यहां तक कि हाल के दिनों में किसानों के आन्दोलन

को व्यापक धारदार बनाने वाले वामपंथी दलों ने भी किसानी के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और बेरोजगारी व मजदूरी को मुख्य मुद्दों में शामिल कर लिया है। सबसे सोचनीय स्थिति देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की है। कांग्रेस

अध्यक्ष राहुल गांधी कई बार किसानों की समस्याओं को उठाए। यहां तक कि संसद भवन में भी उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति पर चर्चा की। जब मध्य प्रदेश और अन्य प्रांतों में किसानों का स्वस्फूर्त आन्दोलन प्रारंभ हुआ तो वहां बिना बुलाए पहुंच गए लेकिन इस चुनावी समर में वे किसान के मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। उनके भाषणों से किसान गायब हैं। हालांकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों के बारे में जरूर चर्चा की है लेकिन राहुल के भाषणों में जिस प्रकार किसान का मुद्दा होता था वह फिलहाल गायब होता दिख रहा है।

आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस पर कतिपय चिंतन की जरूरत है। किसान की स्थिति में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया है, अपितु स्थिति और भयावह हुई है। विगत दिनों पंजाब में आत्महत्या करने वाले किसानों के बच्चों और परिजनों के बीच काम करने वाली किरण कौर ने बताया कि पंजाब में विगत छः महीनों के अंदर कई किसानों ने आत्महत्या की है। वही हाल महाराष्ट्र का भी है और मध्य प्रदेश का भी हाल बेहाल है। इसका सीधा – सा हिसाब है कि जिन राज्यों में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता छीनी, वहां भी किसानों की स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ गयी है। पंजाब की कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की सरकार ने किसानों के लिए घोषणाएं तो कर दी लेकिन उन घोषणाओं का संपादन अधर में है। कर्जमाफी की सारी योजनाएं बड़े किसान उठा रहे हैं, या फिर कांग्रेस के निकट वाले किसानों को योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार की भी नीति कोई किसान समर्थक नीति नहीं कही जा सकती है। यही कारण है कि पंजाब, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के किसान कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक बार फिर से लामबंद होने लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल को इस जमीनी सच्चाई की जानकारी है और यही कारण है कि राहुल किसानों के मुद्दे को उठाकर अपनी पार्टी को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में घाटा नहीं पहुंचाना चाहते हैं।

थोड़ी चर्चा किसानों की स्थिति पर भी करनी चाहिए। हाल ही में जारी एक रपट में बताया गया है कि कृषि आय 15 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गयी है। आर्थिक सहयोग संगठन ने दावा किया है कि वैश्विक स्तर पर कृषि में लागत मूल्यों की तुलना में उत्पाद मूल्य कम मिलने के कारण विगत 17 वर्षों में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे देश के नीति नियंताओं ने हाल ही में औद्योगिक क्षेत्र में और अधिक निवेश का आह्वान किया है। हालांकि तर्क यह दिए जा रहे हैं कि वहां निवेश करने से रोजगार में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में एक बार फिर से संकटग्रस्त कृषि क्षेत्र को नजरअंदाज किया जा रहा है जबकि देश की अधिकतर जनसंख्या आज भी कृषि रोजगार से जुड़ी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि देश की कुल आबादी का 52 प्रतिशत हिस्सा कृषि रोजगार पर आधारित है लेकिन निवेश के मामले में बड़ी तेजी से सरकार कटौती कर रही है। आंकड़ों के अनुसार 2011 – 12 में कृषि निवेश 3.1 प्रतिशत था जो 2016 – 17 में घटकर 2.2 प्रतिशत रह गया। इस सरकारी षडयंत्र में केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीति निर्धाकर ही शामिल नहीं हैं, अपितु प्रतिपक्षी कांग्रेस के रणनीतिकार भी बराबर के हिस्सेदार हैं। और यही कारण है कि किसानों के मुद्दे को इस बार बड़ी चालाकी से दरकिनार किया जा रहा है। इस षडयंत्र में वामदल भी शामिल दिख रहा है। हालांकि कुछ किसान संगठन और किसान की चिंता करने वाले सामाजिक कार्यकर्त्ता किसानों के मुद्दे को आज भी बड़ी तसल्ली से उठा रहे हैं और किसान उनके साथ चलने को तैयार भी है।

आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार किसान का गन्ना बकाया मुद्दा प्रभावी रहेगा और वहां भाजपा बुरी तरह हारेगी, जबकि छत्तीसगढ, ओड़िसा और तेलंगाना में सत्तारूढ़ दल किसानों को रियायत देकर अच्छी खासी सीट जीत लेंगे लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा राजनीतिक पार्टियों के एजेंडों से गायब है। इसका सीधा – सा उत्तर यही है कि राजनीतिक दल किसानों को बुरी तरह मारने की योजना के पैरोकार हैं। हां, जब सत्ता प्राप्त करनी हो तो किसानों को सहलाते हैं और जैसे ही सत्ता प्राप्त हो गयी किसानों को अपने एजेंडे से बाहर कर देते हैं।

इसलिए इस बार के आम चुनाव में किसानों को अपना मुद्दा खुद बनाना पड़ेगा। किसानों को यह तय करना होगा कि आखिर उसके लिए कौन – सी पार्टी अच्छी है और कौन – सी पार्टी उसके खिलाफ। हालांकि भारत में हर पार्टी को कॉरपोरेट चंदा चाहिए। सरकारों को ऐसा माहौल चाहिए कि कोई आन्दोलन न खड़ा हो। नौकरशाहों और पूंजीपरस्थों को संसाधन की लूट में छूट चाहिए। यह सब तभी संभव होगा जब किसान हाड़तोड़ मेहनत कर अन्न उपजाएं और उसे सरकारी दबाव में कौड़ी के दाम बेचे। इससे लोगों को अन्न उपलब्ध होगा और देश में शांति बनी रहेगी। किसानों के बीच काम करने वाले पत्रकार हमीर सिंह बताते हैं कि किसान आखिर क्यों कम कीमत पर अपना उत्पाद बेचे? किसानों को भी अधिकार है कि वह मूल्य का निर्धारण खुद करे। इससे उसे सरकार वंचित कर रही है। इसलिए जो भी पार्टी उसे यह अधिकार दिलाने का वादा करे, किसानों को उसका समर्थन करना चाहिए। यदि इस वादे को कोई पार्टी अपने एजेंडे में शामिल नहीं करती है तो किसानों को अन्य विकल्प की तलाश करनी चाहिए।

अब तो जाग जाईये...वरना 23 मई के बाद लंबी नींद

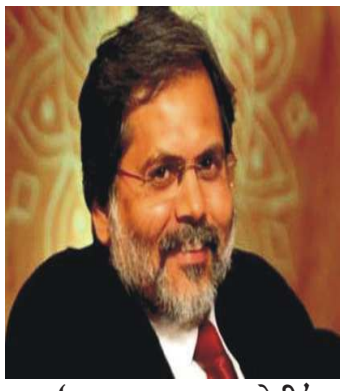

'पुण्य प्रसून बाजपेयी'

जो पाठ मोदी एंड कंपनी कांग्रेस के 70 बरस के नाम पर कर रही है और अपने पांच बरस छुपा रही है। जो मंत्र इंदिरा के गरीबी हटाओ के नारे को जप कर बीजेपी अपने सच को छुपा रही है, यह संकेत है कि लोकतंत्र इतिहास दोहराने को तैयार है। यकीन मानिये भरोसा कांग्रेस पर से भी टूटा और इंदिरा से भी टूटा है और भरोसा मोदी से भी टूटेगा। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटने से पहले सोचना शुरु कीजिये ऐसे जनतंत्र पर किसका भरोसा बचेगा जो सत्ता पाने के लिये आम वोटरों की त्रासदी को खेल बनाता हो।

इंदिरा का नारा गरीबी हटाओ। 1971 का चुनाव और इसी नारे के सहारे शोषित और उपेक्षित समाज की भावनाओं को उभारा गया। भाषण हो, पोस्टर हों, वादे हों, सब कुछ गरीबी हटाओ पर टिका, सत्ता मिली और जीत के तुरंत बाद पूंजीपतियों के संगठन में इंदिरा ने जो भाषण दिया वह उन नीतियों के ठीक उलट था जो गरीबी हटाओ के इर्द गिर्द ताना बाना बुने हुये था और तब पहली बार चन्द्रशेखर ने ही सवाल उठाया कि अगर सरकार वादे पूरे नहीं करती या फिर चुनावी नारों के जरीये लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करती है तो फिर जनतंत्र से लोगों का भरोसा उठ जायेगा। ये बात चन्द्रशेखर ने ''यंग इंडिया'' के संपादकीय में लिखा था लेकिन अब सोचना शुरु किजिये कि इंदिरा का तो एक ही नारा था और आने वाले वक्त में मोदी को कैसे लोग याद करेगें...या फिर याद करने की नौबत ही नहीं आयेगी क्योंकि 2014 में गरीब गुरबों की भावनाओं से जुडे नारों की भरमारे बाद सत्ता पाते ही जिस तरह मुकेश अंबानी के अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी अंबानी हो गये और उसके बाद लगातार देश में जिस तरह नीरव को मोदी होने पर गर्व होने लगा। चौकसी को मोदी के याराने पर गर्व होने लगा। कारपोरेट का खुला खेल चंद हथेलियों पर रेंगने लगा उसमें 2019 का चुनाव भरोसा जगाने वाला चुनाव है या टूट चुके भरोसे में भी जंनतंत्र की मातमपुर्सी करते विपक्ष की रुदन वाला चुनाव है या फिर चुनाव सिर्फ एवीएम मशीन और पूंजी के पहाड़ तले अपराध – भ्रष्टाचार की चादर ओढ़ कर सिर्फ वोटों की गिनती तक के जुनुन को पालने वाला है।

कोई पॉलेटिकल नैरेटिव जो बताता हो मई 2019 के बाद देश किस रास्ते जायेगा। कोई विजन जो समझा दें कि कैसे युवा हिन्दुस्तान की सड़क पर नहीं कल कारखानों या यूनिवर्सिटी या खेत खलिहानों में नजर आयेगा। कोई समझ जो बता दें मंडल – कमंडल और आर्थिक सुधार की उम्र पूरी होने के बाद भारतीय राजनीति को अब क्या चाहिये। या फिर राष्ट्रवाद या देशभक्ति तले सीमा पर जवानों की शहादत और देश के भीतर रायसिना हिल्स पर रौंदे जाते संविधान को ही मुद्दा बनाकर लोकतंत्र का नायाब पाठ याद करने का ही वक्त है। तो क्या लोकतंत्र – जंनतत्र अब सिर्फ शब्द भर है और इन शब्दों को परिभाषित करने की दिशा में देश की समूची पूंजी जा लगी है। और जो सत्ता की नयी परिभाषा को याद कर बोलेगा नहीं वह कभी लिचिंग में, कभी लाइन में, कभी गौ वध के गुनाहगार के तौर पर तो कभी भीड तले कुचल दिया जायेगा और कानून का राज सिर्फ यही संभालने में लग जायेगा कि कोई हत्यारा कहीं अपराधी ना करार दिया जाये। जब सब कुछ आंखो के सामने है तो फिर सोचना शुरु कीजिये एक सौ तीस करोड़ के देश में नब्बे करोड वोटरों के बीच 29 राज्य और सात केन्द्र शासित राज्यों के बीच देश के सामने 15 ऐसे नाम भी नहीं जो लोकतंत्र की तस्वीर लिये फिरते हो। मोदी – शाह, राहुल – प्रियंका, मायावती – अखिलेश, नीतिश – लालू, ममता – चन्द्रबाबू, नवीन – स्टालिन, उद्दव – बादल और उसके बाद सांस फूलने लगेगी कि कौन सा नाम लें जो 2019 के चुनाव में अपनी सीट से इतर प्रभाव पैदा करने वाला है। या फिर लोकतंत्र को जिन्दा रख जनता को मौका दे दे कि जनतंत्र से भरोसा टूटना नहीं चाहिये। इस लोकतंत्र के हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे बरसात में भीग चुके माचिस बेचने वाले के होते हैं। माचिस जला कर खुद में आग की तपन पैदा नहीं करेगा तो मौत हो जायेगी और तपन पैदा कर लेगा तो फिर भूख मिटाने के लिये माचिस बेच कर दो पैसे कमाने की स्थिति भी नहीं बचेगी।

तो क्या 2019 का चुनाव वाकई मोदी – राहुल या सत्ता – विपक्ष के बीच का है या फिर जनता और वोटर के बीच 2019 का जनादेश आकर उलझ गया है। जहां मोदी चुनाव हार चुके हैं और राहुल चुनाव जीत नहीं सकते। लेकिन हार – जीत जनता और वोटरों की ही होनी है। वोटिंग का दिन, घंटे भर की कतार, फिर दो मिनट में एवीएम का बटन और 19 मई तक हर वोटर जीत जायेगा। और 23 मई को जनता हार जायगी।

कल्पना कीजिये या ना कीजिये लेकिन सोचिये आखिर 23 मई के बाद जनता को क्या मिलने वाला है। और जनता अगर 11 अप्रैल से 19 मई के बीच वाकई जाग गई और खुद ही जनतंत्र की राह तय करने निकलने लगी तो फिर 23 मई को लोकतंत्र को बंधक बनाये चेहरों का नहीं जनता का जश्न होगा, पर भरोसा तो टूट चुका है। तो फिर मान लिजिये ये सपने में लिखा गया आलेख है और अब सपना टूट गया।

कल तक वो रीना थी लेकिन आज 'रेहाना' है

कल तक उसके सिर पर पिता का साया था और भाई का प्यार था लेकिन आज उसके पास एक ''शौहर'' है। कल तक वो एक बेटी थी एक बहन थी लेकिन आज वो एक ''शरीके हयात'' है।

''नीलम महेन्द्र''

दिन की शुरुआत अखबार में छपी खबरों से करना आज लगभग हर व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन कुछ खबरें सोचने के लिए मजबूर कर जाती हैं कि क्या आज के इस तथाकथित सभ्य समाज में भी मनुष्य इतना बेबस हो सकता है? क्या हमने कभी खबर के पार जाकर यह सोचने की कोशिश की है कि क्या बीती होगी उस 12 साल की बच्ची पर जो हर रोज बेफिक्र होकर अपने घर के आंगन में खेलती थी लेकिन एक रोज उसका अपना ही आंगन उसके लिए महफूज नहीं रह जाता? आखिर क्यों उस आंगन में एक दिन यकायक एक तूफान आता है और उसका जीवन बदल जाता है? वो बच्ची जो अपने माता पिता के द्वारा दिए नाम से खुद को पहचानती थी आज वो नाम ही उसके लिए बेगाना हो गया। सिर्फ नाम ही नहीं पहचान भी पराई हो गई। कल तक वो रीना थी लेकिन आज ''रेहाना'' है। सिर्फ पहचान ही नहीं उसकी जिंदगी भी बदल गई। कल तक उसके सिर पर पिता का साया था और भाई का प्यार था लेकिन आज उसके पास एक ''शौहर'' है। कल तक वो एक बेटी थी एक बहन थी लेकिन आज वो एक ''शरीके हयात'' है।

यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान से हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण और निकाह कराने की खबरें आई हों। लेकिन हाँ शायद यह पहली बार है जब पाक में रह रहे हिंदुओं के साथ वहां होने वाले किसी अत्याचार की खबर पर भारत के विदेश मंत्री ने सीधे वहां मौजूद भारतीय उच्चायोग से इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी हो। इसके साथ ही भारत सरकार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को इस मामले में आधिकारिक नोट लिख कर वहाँ मौजूद अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए भी कहा है। गौरतलब है कि सिंध से दो लड़कियों के अपहरण की उक्त खबर के कुछ ही देर बाद मुल्तान से भी दो हिंदू लड़कियों के वीडियो सामने आए हैं जिसमें वे सरकार से खुद को कट्टरपंथियों से बचाने की मिन्नत कर रही हैं।

हिंदू लड़कियों को अगवा करके उनसे जबरन इस्लाम कबूल करवा कर उनका निकाह करवा देना पाकिस्तान में कितनी बड़ी समस्या है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इमरान खान ने 2018 के अपने चुनावी भाषणों में यह वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो हिन्दू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

दरसअल आतंकवाद को सरंक्षण देने के मामले में जिस प्रकार पाक पूरे विश्व के सामने बेनकाब हो चुका है उसी प्रकार अब हिन्दू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करने के बाद उनका निकाह करवाने के मामले में भी उनका सच अब धीरे – धीरे दुनिया के सामने आने लगा है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में हर महीने लगभग 20 से 25 लड़कियों का अपहरण कर धर्मांतरण कराया जाता है। और अब तो वहाँ का मानवाधिकार आयोग ही कट्टरपंथियों की इस दलील को खोखला बता रहा है जो अक्सर उनके द्वारा दी जाती है कि अगवा हुई लड़की ने अपनी मर्जी से एक मुसलमान से शादी की है और वो अब अपने पुराने धर्म या परिवार में लौटना नही चाहती।

दरअसल 2010 की अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने स्पष्ट कहा था कि अधिकांश मामलों में हिंदू लड़कियों का अपहरण कर उनके साथ बलात्कार किया जाता है और बाद में उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। आयोग का यह भी कहना है कि यह घटनाएं सिंध प्रांत तक ही सीमित नहीं है बल्कि देश के अन्य भागों जैसे थार, संघार, जैकोबाबाद इलाकों में भी ऐसा हो रहा है। सिंध और इन इलाकों में हिन्दुओं की गिरती हुई जनसंख्या ही अपने आप में वहाँ के हालात के बारे में बयाँ करने के लिए काफी है।

स्थिति यह हो गई है कि अब पाक में मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार और आम लोग भी इस प्रकार की घटनाओं पर अपना आक्रोश व्यक्त करने लगे हैं। वे अपनी ही सरकार को अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा करने में असफल रहने का आरोप लगा रहे हैं। इसी कारण अब पाक में धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग तेज हो गई है। इससे पहले भी 2016 में सिंध विधानसभा में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का बिल पास हुआ था लेकिन कट्टरपंथी संगठनों के विरोध के चलते लागू नहीं हो पाया था। लेकिन अब मौजूदा परिस्थितियों में इमरान खान और उनका ''नया पाकिस्तान'' धर्मांतरण जैसे इस नाजुक मुद्दे पर अपने ही द्वारा जगाई गई पाक आवाम और खास तौर पर वहां के अल्पसंख्यकों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं यह तो समय ही बताएगा। लेकिन उन्हें इस प्रकार नाबालिग और कम उम्र की बच्चियों के धर्मांतरण से उठने वाले कुछ सवालों के जवाब तो देने ही होंगें जैसे, आखिर हर बार सिर्फ लड़कियां या महिलाएं ही क्यों ''अपनी मर्जी'' से धर्मांतरण करती है। कभी कोई लड़का या पुरूष क्यों नहीं? धर्मांतरण की मंजिल आखिर हर बार ''निकाह'' ही क्यों होती हैं? क्यों हर बार लड़की धर्मांतरण के बाद ''पत्नी'' ही बनाई जाती है 'बहन या बेटी' नहीं? क्यों इन लड़कियों को धर्मांतरण के बाद हमेशा 'पति' ही मिलता है भाई या पिता नहीं? और आखरी सवाल 18 साल से कम उम्र के किसी आजाद युवा को अपने देश की सरकार चुनने का अधिकार नहीं है लेकिन एक 'अपहृत' नाबालिग लड़की को धर्मांतरण और निकाह करके अपनी पहचान बदल लेने का अधिकार है? इन सवालों के ईमानदार उत्तर में ही धर्मांतरण की समस्या का समाधान छुपा है।

बेजुबानों की आवाज बने पत्रकार:उपराष्ट्रपति

शिमला/पीआईबी। उउपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि हमारे जैसे प्रगतिशील लोकतांत्रिक देश के लिए, हमारे प्रेस को कुशल और निडर होना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों को समाज के लिए एक दर्पण के रूप में काम करने का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें बेजुबानों की आवाज बनना चाहिए। नायडू नई दिल्ली में पहली मलयालम दैनिक 'दीपिका' के 132वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।

यह कहते हुए कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की उन्नति के लिए एक कुशल और निडर प्रेस होना जरूरी है, नायडू ने पत्रकारों से कहा कि वे वास्तविकता को चित्रित करें, समाचार सामग्रियों को यथावत प्रस्तुत करें, न की बढ़ाचढ़ाकर प्रस्तुत करें, न ही कम करें, न विकृत करें और न ही कोई रहस्योद्घाटन करें। यह कहते हुए कि एक अखबार की गरिमा और प्रतिष्ठा सत्य और निडर रिपोर्टिंग के प्रति उनकी निष्ठा की डिग्री पर टिकी हुई है, उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक व्यक्ति मीडिया से अपेक्षा करता है कि वह न केवल सही रिपोर्ट करे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अन्याय को भी उजागर करे, इस तरह उनके निवारण का मार्ग प्रशस्त होगा।

नायडू ने कहा कि यह आम तौर पर अखबारों और मीडिया का भी कर्तव्य है कि वे मोटे तौर पर सरकार की विकासात्मक पहलों और नीतियों का समर्थन करने के साथ-साथ उसकी कमियों के बारे में भी बताएं, ताकि हमारे देश में प्रशासनिक तंत्र की प्रभावशीलता में सुधार लाने में मदद मिले। उन्होंने मीडिया से ऐसे मामलों पर कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने और नागरिकों को उनके बुनियादी अधिकारों के बारे में जागरूक करके सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को कहा।

चुनाव के समय मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होने की ओर इशारा करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि चुनाव जिस निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुए हैं, उससे तय होता है कि मीडिया कितना निष्पक्ष और जिम्मेदारी से व्यवहार करेगा।

चुनावों के बारे में चर्चा करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ वोट देने की स्वतंत्रता और क्यों और कैसे वोट देना चाहिए, इसका ज्ञान होना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें मतदाता जानकारी आधारित सार्वजनिक बहस में भाग लेते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं।

उपराष्ट्रपति ने मीडिया को अपने कवरेज में उच्च स्तर की व्यवसायिकता, सटीकता और निष्पक्षता बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि चुनावों के समय वे अपने कर्तव्य को बड़ी मुस्तैदी के साथ निभाएं। उन्होंने कहा कि मतदाता को मतदान के अपने महत्वपूर्ण अधिकार के सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए जानकारी दें।

नायडू ने गलत काम करने वालों को सामने लाने के लिए मीडिया को निडर होने को कहा। सकारात्मक सामग्रियों की रिपोर्ट करने में कभी संकोच न करें और हमेशा सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोगों की सराहना करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण घटना के संचालन में आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और जहां भी आवश्यक हो, सकारात्मक और रचनात्मक आलोचना करने से कभी भी न चुकें।

राष्ट्र दीपिका लिमिटेड के अध्यक्ष डॉ फ्रांसिस क्लेटस, दीपिका के मुख्य संपादक, फ्रांसिस बॉबी एलेक्स मन्नमपल्लकल, दीपिका के प्रबंध निदेशक फ्रांसिस मैथ्यू चंद्रनकुनेल, दीपिका के एसोसिएट एडिटर जॉर्ज कल्लीवयालिल और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

सत्ता की विष कन्या

देव राज

सत्ता का साम्राज्य आदि काल से जन-मानस को प्रभावित करता आ रहा है। चाहे विश्व के किसी भी मार्ग पर शासन कोई राष्ट्रपति व प्रधानमन्त्री जैसे सर्वोच्च पद पर हो वह भी सत्ता की विष कन्या के दायरे में आते हैं। आज प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति कौन है इस बात पर ज्यादा ध्यान नही जाता हैं। लेकिन किंग मेकर के कितने अधीन होकर काम करता है इसका ज्यादा महत्व है। ये पद पर आज मोम के पुतले की तरह प्रयोग किये जाते हैं। हमारी पार्टी का विकास जैसे भी होना चाहिये। चाहे देश के गोपनीय दस्तावेज विदेश को बेचने पड़े।

चाहे लाखों लोग बाढ़ में मरे, चाहे भूकम्प या भूख से देश में वीरानी छा जाये मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिये। आज के दौर मे राजनीतिक दलों के नाम अगर कम्पनी के तौर पर प्रयोग किये जाये तो कोई आर्श्चय नही होगा।

अंग्रेजो की इस्ट इंण्डिया कम्पनी की तरह आज राजनीतिक पार्टियां नैतिक मूल्यों का त्याग करके सत्ता रूपी विष कन्या का आलिंगन करने में जुटी रहती हैं। वो किसका हाथ थाम कर सत्ता हासिल कर रही है इस बात से उन्हे कोई लेना देना नही होता। वो हाथ चाहे दाऊद का हो, चाहे राजन का हो, चाहे अन्य कोई माफिया संगठन का हो। बस कुर्सी हाथ लगनी चाहिये फिर देखा जायेगा। ये खेल कितना बड़ रहा है कि आम आदमी भय के साये में जा रहा है। अमीर आदमी और भी सम्पन्न हो रहा है। गरीब परिवार आत्म-हत्या करने मे मजबूर हो गए हैं। राजाओं के राज में एक रियासत में राज की हकुमत चलती थी मगर आज हर विधायक राजा है यहां तक कि पंचायत प्रधान भी राजा से कम नही रह गया है। प्रार्थना पत्र प्रधान से लेकर मुख्यमन्त्री तक लिखते-लिखते रामायण हो जाती है, कुछ एक पार्टी भक्तों को तो नेताओं की आरती उतारते उम्र बीत गई कुछ हाथ न लगा।

वर्तमान काल में ईश्वर पूजा कम और व्यक्ति पूजा ज्यादा बढ़ गई है। सर्दी में गर्मी का मौसम बरसात में सूखा अचानक भूकम्प का प्रकोप, कहीं अचानक ज्वालामुखी फटना आदि देवी प्रकोप दिनों दिन बढ़ रहे हैं। आज के राजा महाराजा इस धरती पर सत्ता रूपी विष कन्या के काल ग्रास हो चुके हैं। आज के इस अस्थिर दौर में कब मंत्री जी सड़क पर आ जायें या कब सड़क वाला मंत्री बन जाए कुछ पता नही चलता।

इस कुर्सी के खेल मे इतनी आसक्ति बढ़ गई है कि 50 वर्ष तक किसी पार्टी में रहने के बाद तुरन्त पार्टी की निष्ठा त्याग कर सत्ता रूपी निष्ठा को हासिल कर लेते हैं।

फिर उसी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं जिससे उनका राजनीतिक जीवन बना था। भला ये देश, समाज का क्या भला करेंगे? सत्ता रूपी कुर्सी ही विष कन्या है उस पर सभी की नजर लगी रहती है भले ही गोली क्यों न चलानी पड़े पर कुर्सी रूपी विष कन्या मेरी हो जायेगी। ये कुर्सी न किसी की है, न रही है ओर न रहेगी।

ये कुर्सी सिर्फ वही संभाल सकते हैं जो न्याय, प्रिय धर्म व त्यागमय प्रवृति से इसका सेवन करते हैं बाकि कुर्सी सभी को सर्वनाश की खाई में धकेल देती है। सत्ता रूपी विष कन्या हजारों, लाखो प्राणियों को मुंह में डाल कर खत्म कर चुकी है। लालच से व्यक्ति का स्वधर्म पतन होता है और समाज व देश का विकास स्वधर्म या समदर्शी होकर ही सभंव है। मनुष्य अपने अन्तकरण की प्रवृति से आगे बढ़ सकता है। कागज की नाव से कोई भी पार नही लग सकता। दृढ़ इच्छा शक्ति व आत्मबल से सभी लोगों पर राज कर सकता है फिर भला कुर्सी रूपी धरती की सत्ता क्या मायने रखती है।

पाठ्यक्रम बनाते समय ज्ञान और कौशल को अधिक महत्व

शिमला/पीआईबी। उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने सभी शैक्षणिक संस्थानों से छात्रों को गुणवत्ता, सस्ती, सार्थक शिक्षा प्रदान करने वाले उत्कृष्टता केंद्र बनने की दिशा में काम करने का आह्वान किया है। यह बताते हुए कि उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को उन्नत करना भारत के जनसांख्यिकीय लाभ को सार्थक करने में एक आवश्यक घटक है, उपराष्ट्रपति ने छात्रों को वैश्विक नौकरी बाजार में सफलता पाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उद्योगजगत के साथ बातचीत करने और काम करने के लिए शैक्षिक संस्थानों का आह्वान किया। उन्होंने उनसे अपेक्षा करते हुए बताया कि छात्रों को रोजगारपरक कौशल के साथ पेशेवर बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए पाठयक्रम तैयार करते समय वे ज्ञान और कौशल को अधिक महत्व दें।

जागरण प्रकाशन समूह द्वारा आयोजित ''रैंकिंग ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एजुकेशनल इंस्टीटयूट्स इन इंडिया'' कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना किसी छात्र और संस्थान के बीच पवित्र विश्वास का विषय होना चाहिए, क्योंकि वे बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ इन संस्थानों में शामिल होते हैं।

नायडू ने शैक्षणिक संस्थानों और उनके प्रबंधन से इस तथ्य पर विचार करने के लिए कहा कि अधिकांश छात्रों के पास पेशेवर व्यावसायिक संस्थानों में अपनी शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं और उन्हें ऋण लेने की जरूरत हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि रैंकिंग से छात्रों और उनके माता-पिता को संस्थान, बुनियादी ढांचे और इसकी शैक्षणिक और अनुसंधान क्षमता के बारे में पूरी जानकारी पाने में मदद मिलेगी।

यह बताते हुए कि देश और हमारे समाज का भविष्य युवाओं के सपनों में आकार ले रहा है, नायडू ने जोर देकर कहा कि हमारे युवाओं को प्रशिक्षित करने और उनमें अत्यधिक मानव संसाधन का उपयोग करने के लिए उच्च मानवीय कौशल प्रदान करने की आवश्यकता है।

उपराष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से संकाय सदस्यों, छात्रों और युवाओं के साथ अपनी बातचीत के बारे में चर्चा करते हुए, नायडू ने कहा कि इस तरह का हर अवसर हमारे लिए बेहद ज्ञानवर्धक और लाभदायक अनुभव रहा है और हमारे युवा छात्रों में आकांक्षात्मक आशावाद मौजूद था। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए ज्ञान तीर्थ रहा है।

भारत के विकास की गाथा और इसकी संभावनाओं के बारे में चर्चा करते हुए, उन्होंने कहा कि नई ऊंचाईयों तक पहुंचने में युवाओं की भागीदारी एक अनिवार्य घटक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्र को एक समावेशी विकास पथ पर ले जाने के लिए शहरी ग्रामीण विभाजन, छिपी हुई भूख, असमानता और विभिन्न स्तरों पर असमानताओं जैसी समस्याओं को दूर करना आवश्यक है। उन्होंने कृषि को अधिक व्यवहार्य और लाभदायक बनाकर ग्रामीण भारत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक

शिमला/शैल। भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के तहत निर्वाचक प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता बढ़ाने व अधिक से अधिक मतदान के उद्देश्य से कसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र में सहायक निर्वाचन अधिकारी नीरज गुप्ता के मार्गदर्शन में जन जागरूकता

अभियान की शुरुआत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मशोबरा, ढली , भटट्राकुफर, मैहली से की गई। इस कडी में मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को EVM , VVPAT के बारे में जागरूक किया गया।

अध्यापकों एंव विद्यार्थियों को अधिक से अधिक मतदान के लिए जागरूक करने की शुरुआत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्मा राजकीय उच्च पाठशाला डाबरी से की गई। स्वीप के नोडल अधिकारी दिलीप वर्मा ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवक व युवतियों को विद्यार्थियों के माध्यम से वोट बनाने का आग्रह किया। उन्होने अध्यापकों एंव विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हैं। यहां का लोकतन्त्र बहुत समृद्ध पारदर्शी है, मतदान द्वारा ही सरकार चुनी जाती है, अत: वोट देना न व्यक्ति का सिर्फ व्यक्ति का कर्तव्य है, बल्कि अधिकार भी है। उन्होने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपेन मत देने के अधिकार को समझना चाहिए। मतदाता लोकतंत्र की रीढ की हडडी होते हैं, अत: मत को समझदारी और सही सोच से, सदउपयोग करने का तरीका जानना चाहिए। उन्होने प्रजातंत्र के मूल्यों को विकसित करने की जरुरतों पर प्रकाश डाला व कहा कि लोकतंत्र वास्तव में अधिकाधिक मतदान से ही मजबूत और समद्ध होता है। उन्होने विद्यार्थियों से कहा कि जो अपने मताधिकार का उपयोग करने नहीं जा रहे उन्हें जगाने की कोशिश करनी होगी तथा मतदाता को मत प्रयोग की ताकत को जानना चाहिए और लोकसभा 2019 के चुनाव में मतदाता निर्भीक होकर बिना लालच के मत का प्रयोग करें । स्वीप कार्यक्रम के तहत बालतंत्र की जानकारी देते हुये कहा कि उन्हे अपने अभिभावकों से एक शपथ-पत्र भरवाकर लाना है जिसमें उन्हे शपथ लेनी है कि वह भारतीय लोकतन्त्र का एक जागरूक निर्वाचक है तथा वह निर्वाचक प्रक्रिया मे भागीदार बनकर लोकतन्त्र को सुदृढ़ करेगे तथा आगामी लोकसभा चुनाव में निर्भीक होकर मतदान का प्रयोग करेंगे। उन्होने कहा कि इस बार पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए VVPAT मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें मतदाता सात सेंकण्ड तक यह देख सकता है कि उसने किसे मत दिया है। इस अवसर पर विद्यार्थियों से बजुर्गो ,युवाओं और महिलाओं को चुनाव में बढ़चढ़ कर भाग लेने के लिये प्रेरित करने की प्रतिज्ञा करवाई। इस अवसर पर नोडल अधिकारी तारा चन्द, मतदान कोष्ठ स्तर अधिकारी के पर्यवेक्षक चन्द्र कांत शर्मा, बूथ स्तर के अधिकारी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुम्मा के प्रधानाचार्य, प्राध्यापक, अध्यापक, अभिभावक, अन्य कर्मचारी छात्र उपस्थित थे ।

एसजेवीएन ने 900 मेगावाट की अरुण-3 जलविद्युत परियोजना के समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

शिमला/शैल। एसजेवीएन अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसजेवीएन अरुण-3 पावर डेवल्पमेंट कंपनी (एसएपीडीसी) के माध्यम से 900 मेगावाट की अरुण-3 जलविद्युत परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है। परियोजना 30 वर्ष की अवधि के लिए बूट आधार पर एसजेवीएन लिमिटेड को प्रदान की गई। कुल परियोजना लागत रू. 7018 करोड़ (नेपाली रू. 11,229 करोड़) होने की संभावना है, जिसमें

विद्युत उत्पादन और पारेषण दोनों भाग शामिल हैं।

एसजेवीएन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, नंद लाल शर्मा ने बताया कि इस परियोजना को 70रू 30 ऋण इक्विटी अनुपात पर वित्त पोषित किया जाएगा। तदनुसार, एसजेवीएन भारतीय रू. 2105 करोड़ (नेपाली रू. 3369 करोड़) का योगदान इक्विटी के रूप में करेगा जबकि भारतीय रू. 4913 करोड़ (नेपाली रू. 7860 करोड़) ऋण का हिस्सा होगा। भारतीय रू. 10,000 करोड़ से अधिक की नेट वर्थ के साथ और लगभग 2,900 करोड़ रुपये के कैश रिजर्व के साथ एसजेवीएन के पास इक्विटी भाग को पोषित करने में वित्तीय रूप से समर्थ है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में देश के सबसे बड़े 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन के निर्माण एवं परिचालन का अनुभव रखने के उपरान्त एसजेवीएन हिमालय की विशिष्टि एवं चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों को निष्पादित करने में तकनीकी रूप से भी सक्षम है।

शर्मा ने आगे बताया कि वित्त पोषण के लिए ऋण के हिस्से के लिए एसजेवीएन ने भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ के साथ समझौता किया है। संघ के अन्य घटक एवरेस्ट बैंक लिमिटेड और एनएबीआईएल बैंक लिमिटेड हैं । बैंकों का समूह भारतीय रू. 4913 करोड़ (नेपाली रू. 7860 करोड़) का कुल टर्म लोन प्रदान करेगा, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक भारतीय रू. 4100 करोड़ (नेपाली रू. 6560 करोड़) प्रदान करेगा, बाकी एवरेस्ट बैंक लिमिटेड और एनएबीआईएल बैंक लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाएगा।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भूतपूर्व प्रधान मंत्री नेपाल पुष्पा कमल दहल, नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. युबा राज खातीवाड़ा, एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नंद लाल शर्मा एवं भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक पी.एन. प्रसाद की गरिमामयी उपस्थिति में किए गए। जबकि एसजेवीएन अरुण-3 पावर डेवलपमेंट कंपनी (एसएपीडीसी) के सीईओ, सतीश शर्मा ने एसजेवीएन लिमिटेड की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर ए.एस. बिंद्रा, निदेशक (वित्त), कंवर सिंह, निदेशक (सिविल), गीता कपूर, निदेशक (कार्मिक) के साथ एसजेवीएन और एसएपीडीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सोलन में शिशु लिंगानुपात 934 से बढ़कर हुआ 960

सोलन/शैल। सोलन जिला का शिशु लिंगानुपात वर्ष 2018 में 960 पहुंच चुका है। पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी पीएनडीटी

एक्ट के तहत गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरके दरोच ने कहा कि 0 से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग में शिशु लिंगानुपात वर्ष 2015 में 934 आंका गया था जो वर्ष 2018 में बढ़कर 960 पहुंच चुका है। ये सकारत्मक बदलाव है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 – 19 के दौरान फरवरी माह तक अधिनियम के तहत कुल 128 निरीक्षण अमल में लाए गए। लेकिन जिले में संचालित किसी भी अल्ट्रासाउंड केंद्र से कोई भी गंभीर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सोलन जिला में कुल 31 अल्ट्रासाउंड मशीनें कार्यशील हैं। जिनमें से सरकारी क्षेत्र में 6 जबकि क्षेत्र में 25 अल्ट्रासाऊंड मशीनें प्रयोग में लाई जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों में लिंगानुपात को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी विभाग द्वारा दी जा रही है। विभाग के स्टाफ को भी इस दिशा में निरंतर कार्य करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सरकारी सदस्यों के तौर पर मेडिकल अधिकारी (स्वास्थ्य) डॉक्टर एनके गुप्ता, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर एमके कपूर, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित महाजन के अलावा जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ गगनदीप, जिला लोक संपर्क अधिकारी रवि वर्मा और उप जिला न्याय वादी चंपा सुरील भी मौजूद रहे।

कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ते के नाम पर युवाओं से किया था छल

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत अर्की धुन्दन में भाजपा युवा मोर्चा सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के एक

वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश मे 26 हजार लाभार्थियों को कौशल विकास भत्ता योजना के तहत 38.54 करोड़ रूपये से अधिक के भत्ते वितरित किये गए। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए प्रदेश के विभिन्न भागों में दो सौ परामर्शी लगाये गये और बेरोजगारी भत्ता के तहत 22407 लाभार्थियों को 17.20 करोड़ रूपये किये गये। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि जयराम सरकार कि ये मात्र एक वर्ष की उपलब्धियां हैं जबकि पूर्व कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के नाम पर मात्र ठगा ही है।

उन्होंने कहा कि देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है ताकि देश सुरक्षित हाथों में रहकर आगे बढ़ सके। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि यह पिछले पांच वर्षो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि यह मोदी का ही जलवा है कि उनके नेतृत्व में पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। मोदी सरकार मे विकास दर बढ कर साढे 7 प्रतिशत हो गई है जबकि कांग्रेस सरकार में ये मात्र 5 प्रतिशत थी। कांग्रेस समय में भारतीय अर्थव्यवस्था 11 वें नम्बर पर थी जबकि आज देश मोदी सरकार के नेतृत्व में 5 वीं नम्बर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि 8 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के सिलेन्डर और 10 करोड़ शौचालय तथा 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रूपये का आयुश्मान बीमा के तहत मुफ्त में इलाज की सुविधाएं देना भाजपा की सरकार में ही सम्भव हो पाया है। यही नहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना के तहत 12 किसानों के खाते में 6 हजार रूपये हर साल अगले 10 सालों तक देने का प्रावधान भी मोदी सरकार ने ही किया है।

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में तो गरीब और गरीब होता गया और भ्रष्टाचार इस हद तक पनप गया कि देश की जनता को लगने लगा कि देश की सारी की सारी करन्सी कुछ भ्रष्ट लोगों के घरों तक सिमट कर रह गयी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आते ही भ्रष्टाचार के सभी अड्डे बंद हो गये और कांग्रेस सरकार में आये दिन होने वाले घोटालों पर अंकुश लगाया है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि देश की जनता नरेन्द्र मोदी पर विश्वास करती है और जनता एक बार फिर नरेन्द्र मोदी को भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनायेगी। उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल की जनता ने भी ठाना है कि मोदी के हाथों को और मजबूत करने के लिए प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जीताकर केन्द्र भेजेगी और प्रदेश के विकास की गति को और अधिक गतिशील करेगी।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण

शिमला/शैल। लोकसभा चुनावों के दौरान किसी भी तरह के राजनीतिक विज्ञापन का प्रमाणीकरण आवश्यक है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विनोद कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रकाशित व प्रसारित होने वाले सभी तरह के राजनीतिक विज्ञापनों का प्रमाणीकरण जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति यानी एमसीएमसी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमसीएमसी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निगरानी रखे हुए है। सभी तरह के विज्ञापनों और पेड न्यूज की श्रेणी में आने वाले समाचारों के खर्च को प्रत्याशियों के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। उन्होंने जिले में संचालित सभी केबल ऑपरेटरों को भी यह निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने केबल नेटवर्क पर ऐसा कोई भी विज्ञापन अथवा ऑडियो विजुअल सामग्री प्रसारित ना करें जिसका प्रमाणीकरण मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) द्वारा ना किया गया हो।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया से भी आग्रह करते हुए कहा कि मीडिया तथ्यों पर आधारित समाचारों को ही प्रकाशित या प्रसारित करें। इस तरह के समाचारों से गुरेज करें जो संविधान और भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के अनुरूप ना हों। किसी भी व्यक्ति या वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत या गुमराह करने वाले समाचार भी प्रकाशित या प्रसारित ना करें। उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को संपन्न करवाने में मीडिया की भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

विनोद कुमार ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर और पैंफलेट इत्यादि के प्रकाशन को लेकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत प्रावधान है कि उन पर प्रिंटर और प्रकाशक का नाम व पता छापना अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए जो भी सामग्री प्रकाशित की जा रही है उसे आदर्श आचार संहिता के अनुरूप ही मुद्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि मुद्रित सामग्री में अवांछनीय एवं भड़काऊ व किसी की भावना को आहत करने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो भारत निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के मुताबिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक प्रत्याशी के लिए चुनावी खर्च की सीमा 70 लाख रुपए तय की गई है।

नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 6अप्रैल को

शिमला/शैल। जवाहर नवोदय विद्यालय पण्डोह में वर्ष 2019-20 के शिक्षा सत्र के लिए छठी कक्षा की प्रवेश चयन परीक्षा 6 अप्रैल को होगी। परीक्षा प्रात: 11 बजे से 1.30 बजे तक ली जाएगी।

जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य दुष्यन्त सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह परीक्षा जिला मण्डी के विभिन्न 20 केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से संबंधित परीक्षा केन्द्र में प्रात: 10 बजे तक पहुंचना सुनिश्चित करने को कहा है। परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी के पास प्रवेश पत्र होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र वैबसाइट http://www.nvsadmissionclassix.inसे डाउनलोड कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि प्रवेश पत्र प्राप्त करने या डाउनलोड करने में यदि कोई समस्या आती है, तो अभ्यर्थी अथवा अभिभावक प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय पण्डोह से उनके कार्यालय दूरभाष 282046 पर प्रात: 9 से 5 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को बिना प्रवेश पत्र रोल नम्बर के परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.co.in

वीरभद्र–सुखराम के मिलन से बदले प्रदेश के सारे राजनीतिक समीकरण

प्रचार के दौरान एक मंच पर दिखेंगे दोनों नेता

शिमला/शैल। पंडित सुखराम और उनके पौत्र आश्रय शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गये हैं बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि उनकी कांग्रेस मे घरवापसी हो गयी है क्योंकि एक लम्बे समय तक यह परिवार कांग्रेस का हिस्सा रहा है। पंडित सुखराम प्रदेश से लेकर केन्द्र तक कांग्रेस में मन्त्री रहे हैं। बतौर दूर संचार मन्त्री जो कुछ उन्होंने प्रदेश को दिया है वैसा योगदान प्रदेश के लिये बतौर केन्द्रिय मन्त्री विक्रम महाजन, शान्ता कुमार और वीरभद्र सिंह का नहीं रहा है। सुखराम के इसी योगदान का परिणाम है कि उनका बेटा अनिल शर्मा प्रदेश में कांग्रेस में भी मन्त्री रहा और आज भाजपा में भी मंत्री है। सुखराम के इसी योगदान के कारण आज कांग्रेस में उनकी घर वापसी भी हो गयी और उनके पौत्र को पार्टी ने मण्डी से लोस प्रत्याशी भी बना दिया है। अब इस वापसी के बाद यह आकलन शुरू हो गया है कि इन चुनावों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

पंडित सुखराम की कांग्रेस में वापसी के प्रभाव का आकलन करने के लिये यह समझना आवश्यक होगा कि इस समय प्रदेश की राजनीतिक स्थिति क्या है और उसमें कांग्रेस और भाजपा कहां खड़े हैं। इस समय प्रदेश की सत्ता भाजपा के पास है और कांग्रेस विपक्ष में हैं कांग्रेस में सबसे बड़ा कद पूर्व मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह का है क्योंकि वह छः बार प्रदेश के मुख्यमन्त्री रह चुके हैं। मुख्यमन्त्री होने के लिये कांग्रेस मे उनके सबसे बड़े प्रतिद्वन्दी पंड़ित सुखराम ही रहे हैं। सुखराम और वीरभद्र में यह टकराव किस हद तक पहुंच गया था इसका गवाह वह सब लोग रहे हैं जिन्होंने 1993 में वीरभद्र समर्थकों द्वारा किया गया विधानसभा भवन का घेराव देखा है। इसी घेराव का परिणाम था कि सुखराम अपने समर्थकों के साथ चण्डीगढ़ बैठे रहे और शिमला में अकेले वीरभद्र की बतौर मुख्यमन्त्री शपथ हो गयी थी। 1993 के इस टकराव का पूरा प्रतिफल सुखराम के खिलाफ खड़े हुए दूर संचार घोटाले और मण्डी में उनके आवास पर सीबीआई छापे में मिले चार करोड़ के रूप में सामने आया। क्योंकि सुखराम ने इस सबको वीरभद्र सिंह और स्व. राजेश पायलट का रचा षडयंत्र करार दिया था। इसी परिदृश्य में सुखराम कांग्रेस से 1997 में बाहर निकले और हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन करके 1998 में वीरभद्र सिंह और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। इसके बाद सुखराम फिर कांग्रेस में शामिल हुए और 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले फिर बाहर हुए और वीरभद्र की सत्ता में वापसी फिर रोक दी। भाजपा में शामिल हुए मण्डी की सभी दस सीटों पर कांग्रेस को हार मिली तथा भाजपा को मण्डी से जयराम के रूप में मुख्यमन्त्री मिला। पंड़ित सुखराम को दूर संचार घोटाले में सजा मिल चुकी है और इसी सज़ा के कारण वह चुनावी राजनीति से बाहर हो गये हैं। लेकिन एसी घोटाले के साये में होते हुए भाजपा दो बार 1998 और 2017 में उनके कारण सत्ता भोग चुकी है। इसलिये भ्रष्टाचार के नाम पर आज भाजपा के पास सुखराम परिवार को कोसने का कोई अधिकार नही बचता है।

इसी के साथ कांग्रेस में जो टकराव एक समय वीरभद्र और सुखराम में था वह आज भूतकाल की बात होने जा रहा है। क्योंकि जहां सुखराम अपने केस के कारण चुनाव राजनीति से बाहर हो गये हैं वही स्थिति कानून के जानकारों के मुताबिक निकट भविष्य में वीरभद्र की होने वाली है। सुखराम का बेटा अनिल आज तीसरी बार मन्त्री बना हुआ है। पौत्र आश्रय को कांग्रेस से लोस टिकट मिल चुका है। इस नाते सुखराम का परिवार प्रदेश की राजनीति में वीरभद्र परिवार के मुकाबले ज्यादा स्थापित है। फिर मण्डी की कांग्रेस की राजनीति में सुखराम परिवार को चुनौती देने वाला कोई बड़ा

नाम शेष नही है। क्योंकि कौल सिंह अगला चुनाव न लड़ने की बात कह ही चुके हैं और उनकी बेटी भी हार गयी थी। इस तरह मण्डी मे पूरी फील्ड इस परिवार के लिये खाली है और इस भविष्य के लिये अनिल को मन्त्री पद दाव पर लगाना कोई बड़ी कीमत नही है। जबकि वीरभद्र का बेटा पहली बार विधायक बना है। उनकी पत्नी राजनीति में स्थापित नहीं हो पायी है। बेटा शिमला ग्रामीण से विधायक बना है क्योंकि रामपुर और रोहडू दोनों ही आरक्षित क्षेत्र हैं। ऐसे में विक्रमादित्य को राजनीति में स्थापित होने के लिये यहीं पर अपनी ज़मीन पुख्ता करनी होगी। इसके लिये आज वीरभद्र और विक्रमादित्य को सबको साथ लेकर चलना उनकी राजनीतिक अनिवार्यता हो जाती है। इस वस्तुस्थिति में आज वीरभद्र के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह पूरी ईमानदारी से सुखराम और आश्रय का सहयोग करें। इस सहयोग के लिये उन्हे रामपुर और किन्नौर से ही इतनी बढ़त सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि अकेले उसी के दम पर आश्रय की जीत का श्रेय उन्हें मिले। क्योंकि हर बार जब भी प्रदेश में कांग्रेस हारी है उसके लिये कांग्रेसी सबसे पहला आरोप वीरभद्र सिंह पर ही लगाते आये हैं। इस आरोप को खारिज करने और बेटे के लिये भविष्य में सहयोग सुनिश्चित करने के लिये आज वीरभद्र सिंह के पास कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। क्योंकि यह आज हर आदमी मान रहा है कि यदि सुखराम और वीरभद्र सिंह इकट्ठे होकर एक साथ एक बार भी पूरे प्रदेश में घूम आये तो 2014 की हार का पूरा बदला ले सकते हैं।

हमीरपुर का फैसला बना कांग्रेस रणनीति की परीक्षा

आश्रय, शांडिल और काजल के नामों की हुई घोषणा

शिमला/शैल। कांग्रेस के मण्डी और शिमला से उम्मीदवारों की हाईकमान द्वारा घोषणा के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने शिमला में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांगड़ा से पवन काजल की उम्मीदवारी का भी ऐलान कर दिया है। राठौर के इस ऐलान के बाद अब केवल हमीरपुर से उम्मीदवार की घोषणा होना बाकी है। हमीरपुर से भाजपा ने वर्तमान सांसद पूर्व मुख्यमन्त्री के बेटे अनुराग ठाकुर को फिर से उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने कांगड़ा और शिमला से उम्मीदवार बदले हैं जबकि प्रदेश चुनाव कमेटी ने सभी वर्तमान चारो सांसदों के फिर से उम्मीदवार बनाने की संस्तुति की थी। प्रदेश कमेटी की इस संस्तुति के बावजूद दो उम्मीदवारों का बदलना जिनमें शान्ता जैसा बड़ा नाम भी शमिल है यह स्पष्ट करता है कि भाजपा हाईकमान की प्रदेश को लेकर मिली सर्वे रिपोर्टो के अनुसार हिमाचल 2019 में 2014 की तरह सुरक्षित नही रह गया है। इन्ही रिपोर्टो के कारण भाजपा ने प्रदेश के चुनाव प्रचार की कमान पूर्व मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार धूमल को सौंपी है। क्योंकि जब शान्ता कुमार को टिकट नही दिया गया है तो यह स्वभाविक है कि इस चुनाव में उनकी पहले जैसी सक्रीयता नही रह जायेगी। शान्ता ने टिकट कटने को गंभीरता से लिया है। सभी जानते हैं कि इस फैसले से पहले उनकी राय नही ली गयी थी। इस तरह इस चुनाव में भाजपा में धूमल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।

ऐसे में जब हमीरपुर से धूमल का अपना बेटा उम्मीदवार है तब स्वभाविक है कि कांग्रेस उन्हें हमीरपुर में ही बांध कर रखना चाहेगी। क्योंकि प्रदेश भाजपा के पास आज भी धूमल से बड़ा कोई नाम नही है। क्योंकि यह धूमल ही थे जिन्होंने अपनी रणनीति से वीरभद्र को अपने दोनों शासनकालों मे ऐसे बांध कर रखा कि आज तक वीरभद्र उस दंश को नही भूल पाये हैं। संभवत: यही कारण है कि हमीरपुर से कांग्रेस के सारे बड़े नेता उम्मीदवार बनने से बचना चाहते रहे हैं। कांग्रेस के इस क्षेत्र के बड़े नेताओं के साथ धूमल के अपरोक्ष में कैसे रिश्ते रहे हैं यह पूर्व में उस समय सामने आ चुका है जब कांग्रेस ने यहां से एक बार क्रिकेटर मदन लाल को प्रत्याशी बनाने का प्रयास किया था। संभवत:यह रिश्ते एक बार फिर सक्रिय भूमिका में आ चुक हैं और इन्ही के कारण हमीरपुर के टिकट का फैसला अभी तक नही हो पाया है। इस समय हमीरपुर से भाजपा के तीन बार सांसद रह चुके सुरेश चन्देल ने कांग्रेस में जाने और फिर कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के संकेत दिये हैं। इन संकेतो के बाद भाजपा ने चन्देल को रोकने के पूरे प्रयास किये हैं। सत्तपाल सत्ती और जयराम ने चन्देल से बैठक की है। इनके बाद अमितशाह से भी चन्देल की बैठक करवाई गयी लेकिन इन सारे प्रयासों का कोई सार्थक परिणाम नही निकल पाया। परन्तु इस सबसे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि यदि कांग्रेस चन्देल को उम्मीदवार बना लेती है तो वह धूमल को हमीरपुर में ही बांधे रखने में बहुत हद तक सफल हो जाती है।

इस परिदृश्य में यह माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने अभी तक चन्देल का विकल्प खुला रखा है। क्योंकि आज जब सुक्खु ने एक साक्षात्कार के माध्यम से हमीरपुर से उम्मीदवार बनने की हामी भरी है उससे यह स्वभाविक सवाल उठता है कि प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष को एक अखबार में साक्षात्कार के माध्यम से उम्मीदवार होने की बात क्यों करनी पड़ रही है। क्या वह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह बताना चाह रहे हैं कि उनकी नीयत पर शक न किया जाये। यदि सुक्खु सही में उम्मीदवार होने के लिये तैयार थे तो उन्हें यह सब चन्देल के नाम की चर्चा उठने से पहले ही कर देना चाहिये था आज जिस हद तक चन्देल का कांग्रेस में आना चर्चित हो चुका है। उसके बाद इसका रूकना चन्देल से ज्यादा कांग्रेस की सेहत के लिये ठीक नही रहेगा। क्योंकि जब कांग्रेस सुखराम को लेने के बाद उनके पौत्र को इसलिये टिकट दे सकती है कि इससे जयराम को उसी के जिले में झटका दिया जा सकता है। तब उसी गणित से चन्देल को शामिल करके हमीरपुर से उम्मीदवार बनना एक कारगर रणनीति की मांग हो जाती है। इस तरह आज कांग्रेस की पूरी रणीनीति की परीक्षा हमीरपुर का फैसला बन गयी है और यह तय है कि इस फैसले का असर प्रदेश की चारों सीटों पर पड़ेगा।